PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Wed, 24 May 2017, Page 15
Width: 50.97 cms, Height: 35.31 cms, a3r, Ref: 33.2017-05-24.106

नए आईआईटी-आईआईएम और एम्स शुरू

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों के दौरान कई नई पहल शुरू की हैं। इसमें नए आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो प्रगति संतोषजनक नहीं है।

2022 तक निरक्षरता दर को 22 से 10% लाने का लक्ष्य रखा गया है

4.5% आबादी ही स्नातक या ज्यादा शिक्षित, 2020 तक दोगुना होगी

2030 तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य

30.5% खर्च स्वास्थ्य सेवा में सरकार का, 2030 तक दोगुने का लक्ष्य

नई दिल्ली | **मदन जैड़ा**

केंद्र सरकार का लक्ष्य हर साल दो करोड़ रोजगार सृजित करने का था, मगर वास्तविकता में आंकड़े दो लाख के भीतर ही सिमटकर रह गए। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था अभी चल रही है, उससे आगे भी रोजगार में बढ़ोतरी के खास आसार नहीं दिख रहे हैं।

शिक्षा क्षेत्र में तीन सालों के दौरान मंत्री बदले हैं। पहले दो सालों में विवाद रहे लेकिन पिछले एक साल से विवाद शांत हैं। शिक्षा नीति अभी तैयार नहीं हो पाई है, इसमें देरी खटकने वाली है। दरअसल, जब एनडीए सरकार सत्ता में होती है विपक्ष को डर रहता है कि अब शिक्षा का भगवाकरण होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नही आई है, जिससे इस बात को बल मिले।

केंद्र ने नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर गांवों के साथ शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का खाका तैयार किया है। आम नागरिकों को एक लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी इसी दिशा में उठाया कदम है।

मिशन इंद्रधनुष की तरह डायरिया-निमोनिया जैसे महंगे टीके निशुल्क लग रहे हैं। बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह पहल अहम है। नई स्वास्थ्य नीति भी बन चुकी है, जिसमें दूरदराज के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर लोगों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मगर डॉक्टरों की भारी कमी है।

सरकार ने महिला कर्मचारियों को अब 12 हफ्ते की बजाय 26 हफ्ते का सवैतनिक मातृत्व अवकाश का कानून भी बनाया है। पहले बच्चे के जन्म पर छह हजार रुपये देने का कदम भी उठाया गया है। बिहार, झारखंड और यूपी में गोरखपुर समेत छह जगहों पर एम्स पर कार्य चल रहा है। प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

> राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह नीति बदलती सामाजिक आर्थिक, प्रौद्योगिकी और उभरती चुनौतियों को देखते हुए बनाई गई है। संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के अलावा हम स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग को भी बढ़ावा देंगे।
>
> **जेपी नड्डा,** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
> (16 मार्च 2017 का बयान)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा।

नई स्वास्थ्य नीति पर जोर

80% आबादी को मुफ्त इलाज के लिए नई स्वास्थ्य नीति

2.5% तक ले जाएगी सरकार स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी के मुकाबले

1.04% ही स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा अभी जीडीपी के मुकाबले

1.5 लाख स्वास्थ्य उप केंद्रों को जल्द कल्याण केंद्रों में बदला जाएगा

60% लोग इलाज के लिए अभी भी निजी अस्पतालों पर निर्भर

नीति की खासियत

- दवा, जांच और इलाज के साथ मरीजों को बीमा का लाभ भी दिया जाएगा
- जिला और उससे उच्च अस्पताल सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएंगे
- ओबामाकेयर जैसी स्वास्थ्य योजना की तैयारी, स्वास्थ्य कर का भी प्रस्ताव
- राज्यों पर नई नीति नहीं थोपी, केंद्रीय स्वास्थ्य नीति एक मॉडल होगी
- 1000 की आबादी पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी

शिक्षा क्षेत्र के सुधार

- **10**वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू सीबीएसई स्कूलों में **2017-18** से
- **41** विषयों की पढ़ाई बंद करने का फैसला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का
- **17** परियोजनाएं शुरू राष्ट्रीय उच्चतर अभियान (रूसा) की, पोर्टल और एप भी लांच किया गया
- **109** केंद्रीय विद्यालयों की पहल और **62** नवोदय विद्यालय खोले गए
- **7** हजार शिक्षक शिक्षण कॉलेजों से हलफनामा लिया गया मूल्यांकन और गुणवत्ता के लिए

तीन बड़े निर्णय

- केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता महानगरों में चार एकड़ से 2.5 एकड़ कर दी गई है। अन्य स्थानों के लिए इसे आठ एकड़ से घटाकर चार एकड़ किया
- आईआईएम को पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी। आईआईएम के कामकाज की समय-समय पर एक स्वतंत्र एजेंसी समीक्षा करेगी
- देश के प्रतिभाशाली युवा नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा दे सकें, इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे अच्छी शोध प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी।

> अगर इसी तरह से संस्थान गलत तरीके से लोगों को डिग्री तथा डिप्लोमा प्रमाण बांटते रहे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। पहले ही लगभग 6500 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया नहीं कराने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी।
>
> **प्रकाश जावड़ेकर,** केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
> (13 मई को स्कूली शिक्षा कार्यशाला में)